कार्यवाही

थाने के टीआई को भी नहीं बताया, साइबर सेल की मदद से पकड़ी 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली

रेत माफिया के खिलाफ एसपी का 'ड्रोन प्लान'

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट पुलिस ने ड्रोन की मदद से बैनगंगा नदी के गोंगलईघाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस एक्शन प्लान को इतना गुप्त रखा गया कि थाने के टीआई को भी इसकी भनक नहीं लगी। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने रेत से भरे सात ट्रैक्टर-ट्राली जब्त किए हैं। पूरा प्लान, एसपी आदित्य मिश्रा ने तैयार किया था।

शनिवार सुबह करीब सात बजे से शुरू हुई ये कार्रवाई दोपहर एक बजे तक चली। पुलिस टीम को देखकर चालक, वाहनों को खड़ा कर भाग निकले। जिसके बाद पुलिसकर्मी ही सातों ट्रैक्टर-ट्राली चलाते हुए कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस अब बिना नंबर के वाहन मालिकों और चालकों का पता कर प्रकरण तैयार कर रही है।

शनिवार तड़के पुलिस को अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने के बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। पहले ड्रोन के माध्यम से उत्खनन और परिवहन

की निगरानी की गई। इसके बाद, अलग-अलग छह टीमें गठित कर एक साथ बैनगंगा नदी के गोंगलईघाट पर छापा मारा गया।

एसपी के निर्देश पर रेत माफिया पर कार्रवाई के लिए निरीक्षक कामेश धूमकेती के नेतृत्व में छह टीम बनाई गईं। इनमें अलग-अलग थानों के सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और आरक्षक शामिल किए गए। इन टीमों में साइबर सेल के चुनिंदा आरक्षकों की विशेष तौर पर शामिल किया गया। हर टीम में 10 लोग शामिल किए गए।

एसपी अभिषेक मिश्रा ने कार्रवाई से पहले हथियारों से लैस टीमों को ये नहीं बताया कि उन्हें कहां और क्या करना है। इसके बाद निरीक्षक कामेश धूमकेती को निर्देश दिए। धूमकेती ने रेतघाट से बाहर निकलने वाले सभी कट पाईंट पर अलग-अलग टीम को तैनात कर दिया। इसके बाद ड्रोन की मदद से अवैध उत्खनन पर नजर रखी। जैसे ही तस्करों ने नदी से रेत लोड करना शुरू किया। ड्रोन से लोकेशन लेने के बाद तकरीबन 12 पुलिसकर्मियों ने एक साथ रेतघाट पर छापा मारा।

पुलिस को देखते ही सातों ट्रैक्टर चालक और मजदूर मौके से भाग गए। जब्ती की कार्रवाई करने के बाद पुलिसवाले खुद ट्रैक्टर-ट्राली लेकर थाने पहुंचे। खास बात यह है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक्शन की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी।

बालाघाट जिले में रेत का करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार होता है। वैनगंगा, बाघ, चनई और अन्य सहायक नदियों के साथ-साथ वनक्षेत्रों से भी रेत के अवैध परिवहन की खबरें अक्सर सामने आती हैं। बालाघाट की रेत अपनी गुणवत्ता के कारण प्रदेश के अन्य जिलों और महाराष्ट्र में भी काफी मांग में रहती है। वर्तमान में जिले में रेत खनन का कोई ठेका नहीं है, इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन जारी है।

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी में अवैध रेत खनन को रोकने में विफल रहने पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि अवैध उत्खनन नहीं रुका तो अर्द्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि अवैध उत्खनन नहीं रुका तो अर्द्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे।

मिशन हार्ट के तहत 2 मई को बैहर में नि:शुल्क हृदय रोग जांच शिविर

नवभारत, बैहर। बालाघाट जिले में बच्चों के हृदय रोगों के उपचार हेतु प्रशासन द्वारा विशेष पहल करते हुए 'मिशन हार्ट' अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप के मार्गदर्शन में यह अभियान आगामी एक सप्ताह तक जारी रहेगा।

अभियान के अंतर्गत 02 मई को शासकीय सिविल अस्पताल बैहर में बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष हृदय रोग जांच एवं निदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में 18 वर्ष या उससे कम आयु के ऐसे बच्चों की जांच की जाएगी, जो दिल की बीमारी या जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) से पीड़ित हैं। यह शिविर 02 मई को सिविल अस्पताल बैहर में प्रात: 10 बजे से प्रारंभ होगा और अपराह्न 04 बजे तक चलेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलप ने बताया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में आयोजित यह शिविर केवल जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा। इस शिविर में मैट्रो हॉस्पिटल जबलपुर के डॉक्टर के एल उमा माहेश्वर शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि इस शिविर में बालाघाट जिले के 3 विकासखंड बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा के हृदय रोग से चिन्ह अंकित लगभग 55 बच्चों को बुलाया गया है, साथ ही ऐसे सभी बच्चे आ सकते हैं जिनको हृदय रोग की समस्या है या उनकी पूर्व में सर्जरी हो चुकी है उनका फॉलो अप भी किया जाएगा एवम शिविर में सभी बच्चों की नि:शुल्क इको जांच भी की जाएगी।

शिविर में बच्चों की इको जांच, उपचार एवं आवश्यकता अनुसार सर्जरी की सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आने-जाने, भोजन, ठहरने एवं दवाइयों की व्यवस्था भी निशुल्क रहेगी। आयुष्मान कार्ड होने या न होने की स्थिति में भी सभी सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी।

डॉ निलय जैन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि हृदय रोग से संबंधित रोगों के प्रति जन समुदाय को जागरूक करने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता है। मरीज की पहचान कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि होठों का नीला पड़ना, खेलते खेलते थक जाना, माथे पर पसीना आना, बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होना, वजन ना बढ़ना, शरीर का विकास उम्र के हिसाब से ना होना, छोटे बच्चे को दूध पीते समय माथे पर पसीना आना, सांस का फूलना, बच्चों को खिलाते समय कठिनाई होना ,चक्कर आना, थकान, बेहोशी और कमजोरी महसूस करना, नाखून विस्तार हो या जीभ पर पीला रंग पड़ जाना, तेज सांस लेना, सांस लेने में कष्ट होना और शारीरिक गतिविधियों असामान्य करना यह सभी लक्षण हृदय रोग से संभावित हो सकते हैं । यदि ऐसा कोई भी लक्षण आप अपने बच्चे में देखें तो उसकी एक बार अवश्य जांच कराएं और हृदय रोग से निजात पाएं।

जिला जेल बालाघाट में स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

नवभारत, बालाघाट। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर के निर्देशानुसार जिला जेल बालाघाट में बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्राणेष कुमार प्राण के मुख्य आतिथ्य में 25 अप्रैल 2026 को किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्राणेष कुमार प्राण ने कहा कि शिविर के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें

आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने बंदियों को नियमित व्यायाम करने और मानसिक तनाव से दूर रहने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने बंदियों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री गौतम सिंह मरकाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सतीश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जितेंद्र मोहन धुर्वे, जेल अधीक्षक श्री रामलाल सहलाम सहित अन्य अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। शिविर के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता योजना, जेल लोक अदालत, लीगल एड क्लीनिक तथा अपील के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। स्वास्थ्य शिविर में जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा 160 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान 6 डिफेंस काउंसिल्स की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने 2 बंदियों को विधिक सहायता एवं 184 बंदियों को विधिक सलाह प्रदान की।

दुर्गम वन क्षेत्रों में 11 केवी केबल लाइन बिछाने का कार्य तेज, बिजली संकट से मिलेगी राहत

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट जिले के सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में लंबे समय से बनी वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा बड़े स्तर पर 11 के.वी. केबल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

कलेक्टर मृणाल मीणा की पहल पर अधीक्षण अभियंता अमित कुमार के निर्देशन में यह कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैहर और बालाघाट संभाग के अंतर्गत आने वाले 14 प्रमुख वन क्षेत्रों में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को बदलकर नई केबल लाइन डाली जा रही है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2.65 करोड़ रुपये बताई गई है। विभाग का मुख्य उद्देश्य इन दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण

विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जहां वर्तमान में लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है।

इस योजना के तहत बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, उकवा सहित बालाघाट के ग्रामीण अंचलों में कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से गंजेसर्रा, मंडवा, डोंगरिया, पीतकोना, चौरिया, जैतपुरी, दड़ेकसा, चीतालखोली, धुनधुनवार्धा, कसंगी, कुआगोंदी, माटे, पालागोंदी, कसई टोला, सर्रा, दुगलई, भूतना, नलेझरी, नरपी, मलकुआ, बरगुड़, नंदौरा, बोदलझोला, पंचेरा, खारा, कोकमा और पोलबतुर जैसे वन क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

इन क्षेत्रों में पहले खुली तारों वाली लाइनें थीं, जिन्हें अब सुरक्षित केबल लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे न केवल वोल्टेज में सुधार होगा, बल्कि जंगली क्षेत्रों में तार टूटने से होने वाले हादसों और बिजली चोरी की घटनाओं पर भी नियंत्रण लगेगा। विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 2025 की शुरुआत में इस कार्य को प्रारंभ किया गया था। बैहर संभाग के अंतर्गत बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्रों में अधिकांश केबलिंग कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि बालाघाट संभाग के किरनापुर और लांजी क्षेत्रों में कार्य अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

कार्य पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों और किसानों को लो-वोल्टेज की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

जिला चिकित्सालय में भगवान श्री सत्य साई बाबा के आराधना दिवस महोत्सव का आयोजन

नवभारत, बालाघाट। 24 अप्रैल को भगवान श्री सत्य साई बाबा का आराधना दिवस का दिन था। आज ही के दिन सन 2011 में भगवान समाधिस्थ हुए थे। इस अवसर पर श्री सत्य साई सेवा संगठन जिला बालाघाट व लालबर्रा द्वारा बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया । यहाँ एक बात गौरतलब है की श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा जिला चिकित्सालय में लगातार सप्ताह में पांच दिन वृहद् नारायण सेवा की जाती है जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय में एडमिट मरीजों के साथ रहने वाले उनके परिजनों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था कर नारायण सेवा की जाती हैद्य जिले मे श्री सत्य साई सेवा संगठन में करीब 60 समितियाँ है, और प्रतिदिन एक समिति यह नारायण सेवा की व्यवस्था कर यह सेवा करती है, इस प्रकार एक समिति का सेवा करने का नम्बर करीब ढाई महीने में एक बार आता है, और इसमें संगठन के जिले से करीब 2500 से 3000 परिवार सीधे सीधे शामिल होते हैं, जिसमें वे पांच - पांच फूड पैकेट जिसमें पांच रोटी व सब्जी होती हैं इकट्ठा कर निरंतर यह सेवा कर रहे है और भगवान् के पिछले साल 2025 के आराधना दिवस से अर्थात एक वर्ष से यह सेवा जिला चिकित्सालय में निरंतर निर्बाध गति से बिना किसी हो हल्ला या प्रचार के चल रही है जिसमे संगठन के पुरुष सदस्य व महिला सदस्य दोनों की सहभागिता रहती है. यह जिले या प्रदेश में एक अनूठा उदाहरण है द्य आज इसी सेवा के एक वर्ष पूर्ण होने पर जिले के संगठन की सभी समितियों नें एक साथ उपस्थित होकर एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन कर वृहद नारायण सेवा की जिसमे सिविल सर्जन श्री निलय जैन की भी उपस्थिति रही।

मध्य प्रदेश सरकार का केबिनेट निर्णय मतभेद पूर्ण : बाविसताले

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं शिक्षक संघ पेंशन प्रकोष्ठ बालाघाट के संरक्षक श्री शिवाजी बाविसताले ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में लिये गये शासकीय कर्मचारी से उनके मूल वेतन से एक पर्सेंट (1%) प्रीमियम काट कर उन्हें 20 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले निर्णय को स्वागत योग बताया हैं किंतु वही पेंशनधारकों को इसी सुविधा के लिए उनकी पेंशन से चार परसेंट (4%) की मासिक प्रीमियम काटे जाने का पुरजोर विरोध करते हुए, सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने एवं उनसे भी एक पर्सेंट ही समान मासिक प्रीमियम लेकर ही 20 लाख तक का समान कैसे इलाज दिए जाने हेतु अपने निर्णय में संशोधन किए जाने की निवेदन पूर्ण मांग की गई है ताकि पेंशन धारकों के साथ उचित न्याय हो सके क्योंकि वृद्धावस्था में पेंशन भोगियों से कैशलेस इलाज के नाम पर उनकी पेंशन से चार प्रतिशत मासिक रूप से वसूल कर लेना यानी वृद्धावस्था में उनके सिर पर लाठी पटकने जैसा है जो उनकी सहनशक्ति की सीमा से बाहर होगा।

बाविसतालेजी ने आगे कहा की सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर संशोधन नहीं करती है तो प्रदेश भर के समस्त पेंशन धारकों के साथ मिलकर इस विषय पर सरकार के विरोध में बड़े आंदोलन, की रणनीति बनाई जाएगी एवं प्रदेश भर के सारे वरिष्ठजन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी।

मलाजखंड में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों का निरीक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी तेज

नवभारत, मलाजखंड। नगर पालिका परिषद मलाजखंड में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया।

निरीक्षण के दौरान कचरा संग्रहण वाहनों की कार्यप्रणाली, साफ-सफाई की स्थिति, गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण (सेग्रीगेशन) तथा निर्धारित रूट पर नियमित संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में समयबद्ध तरीके से घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, जिससे नागरिकों को

बेहतर स्वच्छता सेवाएं मिल सकें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शहरों का मूल्यांकन घर-घर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण और समग्र स्वच्छता प्रबंधन के आधार पर किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों में सुधार की आवश्यकता भी सामने आई, जिस पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों को जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ कार्य करने और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

सीएमओ दिनेश बाघमारे ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों और नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। नगर पालिका द्वारा निरंतर निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि स्वच्छता व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे और नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाया जा सके।

मॉयल वित्तीय वर्ष 2026 में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर,19 .07 टन का उत्पादन, भरवेली का 3 .40 लाख टन का योगदान

नवभारत, भरवेली। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली , जिसकी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में कुल 9 खदानें संचालित हैं, ने बीते वित्तीय वर्ष में उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। कंपनी की यह उपलब्धि न केवल उसकी कार्यक्षमता को दर्शाती है, बल्कि भारत के इस्पात क्षेत्र में उसकी मजबूत भूमिका को भी प्रमाणित करती है।

हमें यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 18.02 लाख मीट्रिक टन (ख्ख्) के उत्पादन से आगे बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2026 में 19.07 लाख मीट्रिक टन (ख्ख्) का उल्लेखनीय आंकड़ा हासिल किया है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि निरंतरता, समर्पण और उन सभी हितधारकों के विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उत्पादन में भरवेली खदान का योगदान 3.40लाख टन का रहा ।जिसका श्रेय स्थानीय प्रबंधन ने कामगार, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग के टीम वर्क को दिया है ।ये रिकार्ड उत्पादन हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं।

यह उपलब्धि समर्पण, निरंतरता और भारत के इस्पात क्षेत्र की मजबूती को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का रिकॉर्ड बिक्री प्रदर्शन परिचालन उत्कृष्टता का प्रमाण है और राष्ट्र के विकास को गति देने की उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए, कंपनी एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सफलता के पीछे कंपनी की टीम की कड़ी मेहनत, दूरदर्शी रणनीति और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का अहम योगदान है। प्रत्येक कर्मचारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया, जिससे उत्पादन और बिक्री में यह सकारात्मक वृद्धि संभव हो सकी। साथ ही, ग्राहकों और सहयोगी संस्थाओं का विश्वास भी इस उपलब्धि की मजबूत नींव रहा है।

वर्तमान प्रतिस्पर्धी वातावरण में निरंतर प्रगति करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कंपनी ने इसे अवसर में बदलते हुए नवीन तकनीकों को अपनाया और कार्यप्रणालियों में सुधार किया। दक्षता बढ़ाने के इन प्रयासों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि न केवल संगठन के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे खनन और इस्पात क्षेत्र के लिए प्रेरणा भी है। आने वाले समय में भी कंपनी इसी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अग्रसर रहेगी

दिन-रात धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध खनन, प्रशासन मौन

माफिया के हौसले बुलंद, पूरा कटंगी क्षेत्र रेत माफिया के कब्जे में, कौन है इनके पीछे, चर्चा जोरों पर

कटंगी/तिरोड़ी, नवभारत 25 अप्रैल। बालाघाट जिले के तिरोड़ी और कटंगी क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक चरम पर पहुंच गया है। बावनथड़ी, खरपड़िया नाला, हीरापुर, बम्हनी, बड़पानी और कटंगी क्षेत्र की चंदन नदी के रेत घाटों पर दिन-रात मशीनों से अवैध खनन जारी है।

स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत से यह काला कारोबार बेखौफ चल रहा है, जिससे शासन को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व की चपत लग रही है। तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाली बावनथड़ी नदी, खरपड़िया नाला, हीरापुर, बम्हनी रेत घाट और हरदौली रेत घाट से हर रात सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर अवैध रेत भरकर

निकलते हैं।

नदी में जेसीबी से हो रहा रेत का उत्खनन

क्षेत्र के नागरिकों के अनुसार माफिया पहले नदी से जेसीबी से रेत का उत्खनन करते हैं। फिर उसे ट्रैक्टरों में भरकर थानों और चौकियों के सामने से बेखौफ गुजारते हैं। बम्हनी नदी पर इसे बड़े डंपरों में लोड कर महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। दिन में भी बावनथड़ी नदी में मशीनों के जरिए रेत निकाली जा रही है और आसपास के गांवों में डंप की जा रही है।

डंपर और ट्रैक्टर रात होते ही सक्रिय हो जाते हैं

स्थानीय ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नदियों से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। डंपर और ट्रैक्टर रात होते ही सक्रिय हो जाते हैं। थाने-चौकी के सामने से गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। प्रशासन की चुप्पी से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इन माफियाओं के पीछे कौन है, जिनके दम पर पूरा कटंगी क्षेत्र इनके कब्जे में है।

रेत माफिया को पुलिस व खनिज विभाग का संरक्षण

आरोप है कि रेत माफिया को पुलिस और खनिज विभाग का पूरा संरक्षण प्राप्त है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति होती है। नदी बचाओ का दम भरने वाले सामाजिक संगठन भी खामोश रहकर तमाशबीन बने हुए हैं।

क्या बोले खनिज अधिकारी पाटिल

क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस संबंध में खनिज अधिकारी पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा, 'रेत के अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित जानकारी आपसे मिली है। संबंधित थाने के टीआई और तहसीलदार से बात कर कार्रवाई कराते हैं।'

शासन को रोजाना लाखों की चपत

नियमानुसार रेत खनन के लिए रॉयल्टी पर्ची और ई-टीपी अनिवार्य है। एक ट्रैक्टर रेत की सरकारी रॉयल्टी करीब 700-1000 रुपये है। डंपर की 4000-5000 रुपये। सूत्रों का दावा है कि रोजाना 50 से अधिक डंपर और 200 से अधिक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत ले जा रहे हैं। इस हिसाब से शासन को रोजाना 4 से 5 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।